स्टेट ऑफ जे. एंड के.

बनाम

वसीमहमद मलिक @हामिद और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1743/2009)

1 जुलाई, 2015

[ए. के. सिकरी और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987: धारा 15-बम विस्फोटों के तहत आवश्यकता-विस्फोट के परिणामस्वरूप 8 व्यक्तियों की मौत हो गई और 18 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए-टाडा अधिनियम की धारा 3,4 के तहत आरोप पत्र; आई. पी. सी. की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू. एस. 302,307 और 34; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5-प्रतिवादी-अभियुक्त यू. एस. द्वारा किया गया इकबालिया बयान। टाडा अधिनियम की धारा 15 जिसमें उसने अपनी और अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में स्वीकार किया-पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान, पुलिस अधीक्षक-निचली अदालत ने इस आधार पर इकबालिया बयान को खारिज कर दिया कि यह हिंदी में दर्ज किया गया था। उत्तरदाताओं की भाषा में नहीं और दोनों उत्तरदाताओं को बरी कर दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः

अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्वीकार करने वाला अभियुक्त पूछताछ की रेखा को नहीं समझता था या कि रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद उसे स्वीकारोक्ति की सामग्री को समझने के लिए नहीं बनाया गया था-इकबालिया बयान में अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार किया और उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन किया-इसलिए उसकी रिहाई को दरकिनार कर दिया गया है-अन्य अभियुक्त के संबंध में, अभियुक्त को स्वीकार करने के इकबालिया बयान के अलावा, साजिश और उसके निष्पादन में उसकी भूमिका के संबंध में पुष्टि भेजने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया था-इसलिए, उसके बरी होने की पुष्टि की जाती है-अपील-बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील-रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू एस 302,307 और 34।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1. कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए टाडा अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत दर्ज एक स्वीकारोक्ति निर्माता, उसके सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमे में स्वीकार्य है, धारा 15 (1) के प्रावधान में निर्धारित शर्त के अधीन। इस तरह के कबूलनामे को सबूत के मूल टुकड़े के रूप में लिया जाता है और निर्माता, सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता को दोषी ठहराने के लिए आधार या आधार बन

सकता है। तथापि, जहाँ तक सह-अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के उपयोग का संबंध है, विवेक के नियम के लिए न्यायालय को उस पर तब तक भरोसा नहीं करना होगा जब तक कि सामान्य रूप से अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। [पैरा 13) [1100-एच; 1101-ए-सी] डी

2. टाडा नियमों के नियम 15 (1) में कहा गया है कि स्वीकारोक्ति "हमेशा उस भाषा में दर्ज की जाएगी जिसमें ऐसी स्वीकारोक्ति की जाती है और यदि वह व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए या नामित न्यायालय की भाषा में उपयोग की जाएगी।" "निश्चित रूप से" अभिव्यक्ति से ही पता चलता है कि नियम के तहत आवश्यकता विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। वर्तमान मामले में रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है कि कबूल करने वाले आरोपी 'जी. एन.' को पी. डब्ल्यू. 1 को वैधानिक चेतावनी और सोचने का समय दिए जाने से पहले पेश किया गया था। उन्हें सब कुछ समझाया गया और उसके बाद ही उनके अंगूठे का निशान लिया गया। अगले अवसर पर, जब कबूल करने वाले आरोपी को फिर से गवाह के सामने पेश किया गया, तो स्वीकारोक्ति दर्ज होने के तुरंत बाद उसे फिर से समझाया गया, पढ़ा गया और उसके बाद ही अंगूठे का निशान लिया गया। इन दो अवसरों पर रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी स्तर पर, न ही उस स्तर पर जब गवाह बक्से में था, रिकॉर्ड में कुछ भी

नहीं था, या यहां तक कि एक सुझाव भी था कि कबूल करने वाले आरोपी को स्वीकारोक्ति की सामग्री समझ में नहीं आई थी या उसे समझाया नहीं गया था। स्वीकारोक्ति की सामग्री से यह भी पता चला कि कई दावे कबूल करने वाले आरोपी के लिए व्यक्तिगत थे जो रिकॉर्डिंग अधिकारी के साथ उचित बातचीत के बाद ही एकत्र किए जा सकते थे। स्वीकार करने वाले आरोपी और रिकॉर्डिंग अधिकारी के बीच संचार के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है, हिंदी भाषा में स्वीकारोक्ति की ऐसी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से नियम की आवश्यकता के अनुरूप है। निचली अदालत द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि 'जी. एन.' पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते, उसकी भाषा उर्दू होनी चाहिए और इसलिए उर्दू के अलावा किसी अन्य भाषा में स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग को अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए, गलत है। इस संबंध में निचली अदालत द्वारा किया गया आकलन पूरी तरह से गलत और रिकॉर्ड के खिलाफ था। [पेरा 14,15] [1101-डी-एच; 1102-ए-सी, डी]

3. स्वीकारोक्ति की सामग्री से पता चलता है कि उसने साजिश रचने से लेकर उसके निष्पादन तक अपने अपराध और अपनी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। कबूल करने वाले आरोपी ने साजिश रचने के बाद से विभिन्न चरणों के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे उसने सीमा पार से विस्फोटक सामग्री को ले जाने में मदद की और फिर

उसे गड्ढों में डाल दिया, स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर मुख्य सड़क पर खोदा। बमों का परिणामी विस्फोट जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोहों के साथ किया गया था, निश्चित रूप से समारोहों को बाधित करने और आम लोगों और विशेष रूप से उत्सव के समय एकत्र हुए लोगों को आतंकित करने के लिए बनाया गया था। साजिश, निष्पादन और उसे सुगम बनाने में आरोपी 'जी. एन.' की संलिप्तता पूरी तरह से सामने आई है। एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति सबूत का एक ठोस टुकड़ा है और उसकी दोषसिद्धि इस तरह के स्वीकारोक्ति पर ही आधारित हो सकती है। इसलिए, 'जी. एन.' उन अपराधों का दोषी था जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। हालाँकि, अन्य अभियुक्त 'डब्ल्यू. ए. एम.' के संबंध में, 'जी. एन.' के इकबालिया बयान के अलावा, जिसे सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान कहा जाता है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया था जो साजिश और उसके निष्पादन में उसकी भूमिका के संबंध में पुष्टि कर सके। जैसा कि 'डब्ल्यू. ए. एम.' के संबंध में दर्ज किया गया है, बरी किए जाने के निष्कर्ष को उलटने का कोई औचित्य नहीं था। [पैरा 16 और 17] [1102-एफ-एच; 1103-ए, सी-ई]

राज्य बनाम नलिनी और अन्य (1999) 5 एस. सी. सी. 253: 1994 (2) एस. सी. आर. 375-पर निर्भर था।

कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 3 एस. सी. सी. 569:1999 (3) एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1999 (3) एस. सी. आर. 1 निर्दिष्ट पैरा 12

1994 (2) एस. सी. आर. 375 पर निर्भर था पैरा 12

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 2009 का 1743

टाडा (पी) अधिनियम, 1987 जम्मू के तहत नामित न्यायालय, जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अंतिम निर्णय और आदेश से फाइल सं. 26/चालान।

अपीलार्थी के लिए पी. के. डे, एस. सैनी, के. एल. जंजीनी, बी. वी. बलरामदास।

उत्तरदाताओं के लिए दुष्यंत पाराशर।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

उदय उमेश ललित, जे.

1. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 19 के तहत यह अपील तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी फाइल संख्या 26/चालान

में अधिनियम के तहत नामित न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अधिनियम की धारा 3 और 4, रणबीर दंड संहिता की धारा 302,307 और 34 के साथ पठित धारा 120-बी और 1995 की प्राथमिकी संख्या 12 से उत्पन्न विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 के तहत अपराधों के प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया है।

2. गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 26.01.1995 पर लगभग 10 बजेः जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम में सुबह 20 बजे, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, जनरल के. वी. कृष्ण राव, उच्च गणमान्य व्यक्तियों, वी. आई. पी., सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और सम्मानित नागरिकों सहित लगभग 40,000 लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे, जब सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के स्थल पर, मंच के पास और मुख्य सड़क पर, स्टेडियम के बाहर तीन शक्तिशाली बम विस्फोट हुए, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की मौत हो गई, और अठारह लोगों को गंभीर चोटें आईं और समारोह में व्यवधान पैदा हुआ। घटना के तुरंत बाद उक्त बम विस्फोटों के संबंध में पुलिस स्टेशन नौबाद, जम्मू (जेएंडके) की 1995 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 दिनांक 26.01.1995 दर्ज की गई थी। जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी.

आई.) को दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था और नियमित मामला संख्या आर. सी. 1 (5)/95-एस. आई. यू. वी. को सी. बी. आई. में 31.01.1995 पर दर्ज किया गया था।

3. सी. बी. आई. द्वारा जाँच अपने हाथ में लेने के बाद, एक मोहम्मद इरफान को 07.04.1995 पर गिरफ्तार किया गया। 09.04.1995 पर उन्होंने खुलासा बयान दिए जिससे कुछ बरामदगी हुई। 24.04.1995 पर कहा गया कि मोहम्मद इरफान ने एक इकबालिया बयान दिया जिसे पी. डब्ल्यू. 2 शरद कुमार, एस. पी. सी. बी. आई. द्वारा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रभाव सेः

क) अभियुक्त मोहम्मद इरफान, आईएसआई, पाकिस्तान के मेजर तारिक, एचएम, मुजफ्फराबाद के कमांडर अहमद हसन, एचएम, सियालकोट के कमांडर मेबूब-उल-हक, अमीर-उल-हक, नायब कमांडर, एचएम और जिया कश्मीरी और अन्य अज्ञात लोग 26.12.1994 पर जमात-ए-इस्लामी, मॉडल टाउन, सियालकोट, पाकिस्तान के कार्यालय में एकत्र हुए थे और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जम्मू शहर में आतंक फैलाने के उद्देश्य से राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को मारने की साजिश रची थी। उक्त साजिश को आगे बढ़ाते हुए, आरोपी मोहम्मद इरफान, मेनबूब-उल-हक और

अहमद हसन ने सियालकोट कैंट के लंगरियाली गांव के पास स्थित आई. एस. आई. के कार्यालय का दौरा किया। पाकिस्तान ने 26.12.1994 पर मेजर तारिक, मेजर इब्राहिम, कैप्टन फरहान, आई एस आई, पाकिस्तान के सूबेदार अनवर और वसीम अहमद @हामिद पुत्र जलालुद्दीन मलिक निवासी/ओ अस्थान मोहल्ला, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर के साथ बैठक की और योजना बनाई। उपरोक्त आपराधिक साजिश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने इसे लगाने के लिए सीमा पार जम्मू में दो पूर्व निर्धारित समय बम ले जाने का फैसला किया, एक मंच के पास और दूसरा एम. ए. एम. स्टेडियम जम्मू के मंडप के पास और इस कार्य के लिए मोहम्मद इरफान और गुलाम नबी को प्रतिनियुक्त किया।

दिनांक 23.12.1994 को 11:00 बजे आई एस आई ऑफिस सियालकोट मे मोहम्मद इरफान और वसीम अहमद को बमों और उनके कामकाज और संचालन के बारे में जानकारी दी गई, जिन्हें एमएएम स्टेडियम में लगाया जाना था। उन्हें बमों को पानी से बचाने और रात होने के बाद उन्हें स्टेडियम में लगाने, प्रत्येक बम के लिए दो डेटोनेटर लेने, गड्ढे खोदने के लिए खुरपा ले जाने और स्थल पर बम लगाने का कोई सुराग न छोड़ने के निर्देश भी जारी किए गए थे। उन्हें यह भी बताया गया कि बम पहले से ही सेट किए गए थे ताकि गणतंत्र दिवस समारोह के समय 26.01.1995 पर विस्फोट किया जा सके। कैप्टन फरहान ने

मोहम्मद इरफान और वसीम अहमद को 3,000/- रुपये और गुलाम नबी को भारतीय मुद्रा में 2,000/- रुपये दिए और मोहम्मद इरफान को एक बोरी भी दी जिसमें उन्होंने अपने जूते, पतलून, शॉल और पिस्तौल रखे। मेजर इब्राहिम ने मोहम्मद इरफान और वसीम अहमद को काले पॉलिथीन और हरे रंग के बोरों में विधिवत लिपटे 5-5 किलोग्राम का एक बार का बम प्रदान किया। 28.12.1994 को वे सभी आई. एस. आई. कार्यालय, सियालकोट से निकले और लगभग 10 बजे चेक पोस्ट झुमियां पहुंचे। सूबेदार अनवर और महबूब-उल-हक सियालकोट लौट आए, जबकि मोहम्मद इरफान, वसीम अहमद और गुलाम नबी सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस गए और जम्मू शहर के बाहर तवी नदी के पास बमों और खुरपा को छिपा कर रखा।

ई) मोहम्मद इरफान, महबूब-उल-हक, आमिर उल-हक, अमजद और 2/3 अन्य कश्मीरी लड़के जमात-ए-इस्लामी, सियालकोट के कार्यालय में मौजूद थे। वे जम्मू में बम विस्फोटों, वी. आई. पी. और आम जनता के मारे जाने की खबर का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे उन्हें एमएएम स्टेडियम में हुए विस्फोटों की खबर मिली, जिसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद, मेजर तारिक, कैप्टन फरहान, सूबेदार अनवर ने मोहम्मद इरफान, वसीम अहमद और महबूब-उल-हक को आईएसआई कार्यालय, सियालकोट बुलाया और बम लगाने के

लिए उनकी प्रशंसा की और घोषणा की कि उनका मिशन सफल रहा है, भले ही जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल भाग गए थे। मोहम्मद इरफान पर वसीम अहमद और महबूब-उल-हक ने जमाई इस्लामी, मुजफ्फराबाद के कार्यालय का दौरा किया और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन से मुलाकात की, जिन्होंने घोषणा की कि उनका मिशन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाना था जो एमएएम स्टेडियम में बम विस्फोटों से पूरा हुआ। सलाउद्दीन को एक ढाल और दस हज़ार रुपये मोहम्मद इरफान और वसीम अहमद को दिये ।

4. जाँच पूरा होने के बाद, विशेष न्यायाधीश, नामित टाडा अदालत, जम्मू (जे एंड के) की अदालत में यू/एस 120-बी आर. पी. सी. आर/डब्ल्यू विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 242,34,307 आर. पी. सी., 4 और 5 और अधिनियम की धारा 3 (2), 4 और 6 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। मोहम्मद इरफान @अनवर, एक पाकिस्तानी नागरिक और अन्य फरार आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जबकि मामला निचली अदालत के समक्ष लंबित था, गुलाम नबी गाइड को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 25.10.1995 पर गिरफ्तार किया था। सी. बी. आई. द्वारा एक उचित आवेदन करने पर, गुलाम नबी गाइड की हिरासत सी. बी. आई. को 04.12.1995 पर दी गई। हिरासत में रहते हुए, गुलाम नबी गाइड ने एक इकबालिया बयान दिया जो पी. डब्ल्यू. 1 एस. के. भटनागर पुलिस

अधीक्षक, सी. बी. आई. द्वारा यू/एस. पर दर्ज किया गया था। अधिनियम की धारा 15 जिसमें उसने मोहम्मद इरफान, वसीम अहमद मलिक उर्फ हामिद, मेजर तारिक, मेजर इब्राहिम, मेजर आमिर, कैप्टन फरहान, सूबेदार अनवर (सभी आईएसआई, पाकिस्तान), अहमद हसन, एचएम, सियालकोट के कमांडर, अमीर-उल-हक, नायब कमांडर, एचएम सियालकोट और जिया कश्मीरी निवासी कुपवाड़ा, जम्मू में एमएएम स्टेडियम, जम्मू में हुए विस्फोटों की आपराधिक साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसलिए उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, एक जेलब्रेक में कहा गया कि मोहम्मद इरफान उच्च सुरक्षा वाली जेल से भाग गया। जबकि मुकदमा लंबित था और समापन चरण में पहुंच गया था, वसीम अहमद मलिक नाम के एक अन्य आरोपी, जिसे फरार आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया था, को 15.01.2009 पर गिरफ्तार किया गया था। चूंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद इरफान और गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयानों के रूप में पर्याप्त सबूत थे, इसलिए वसीम अहमद मलिक को सभी प्रासंगिक सामग्री की प्रतियां प्रदान की गईं और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार केवल दो अभियुक्तों यानी गुलाम नबी गाइड और वसीम अहमद मलिक, वर्तमान उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाया गया, जबकि अन्य फरार रहे।

4. जाँच पूरा होने के बाद, विशेष न्यायाधीश, नामित टाडा अदालत, जम्मू (जे एंड के) के न्यायालय में यू/एस 120-बी आर. पी. सी. आर/डब्ल्यू विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 242,34,307 आर. पी. सी., 4 और 5 और अधिनियम की धारा 3 (2), 4 और 6 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। मोहम्मद इरफान @ अनवर, एक पाकिस्तानी नागरिक और अन्य फरार आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जबकि मामला निचली अदालत के समक्ष लंबित था, गुलाम नबी गाइड को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 25.10.1995 पर गिरफ्तार किया था। सी. बी. आई. द्वारा एक उचित आवेदन करने पर, गुलाम नबी गाइड की हिरासत सी. बी. आई. को 04.12.1995 पर दी गई। हिरासत में रहते हुए, गुलाम नबी गाइड ने एक इकबालिया बयान दिया जो पी. डब्ल्यू. 1 एस. के. भटनागर पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. द्वारा अधिनियम की धारा 15 पर दर्ज किया गया था। जिसमें उसने मोहम्मद इरफान, वसीम अहमद मलिक उर्फ हामिद, मेजर तारिक, मेजर इब्राहिम, मेजर आमिर, कैप्टन फरहान, सूबेदार अनवर (सभी आईएसआई, पाकिस्तान के), अहमद हसन, एचएम, सियालकोट के कमांडर, अमीर-उल-हक, नायब कमांडर, एचएम सियालकोट और जिया कश्मीरी निवासी कुपवाड़ा, जम्मू में एमएएम स्टेडियम, जम्मू में हुए विस्फोटों की आपराधिक साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसलिए उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, एक जेलब्रेक में कहा गया कि मोहम्मद इरफान

उच्च सुरक्षा वाली जेल से भाग गया। जबकि मुकदमा लंबित था और समापन चरण में पहुंच गया था, वसीम अहमद मलिक नाम के एक अन्य आरोपी, जिसे फरार आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया था, को 15.01.2009 पर गिरफ्तार किया गया था। चूंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद इरफान और गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयानों के रूप में पर्याप्त सबूत थे, इसलिए वसीम अहमद मलिक को सभी प्रासंगिक सामग्री की प्रतियां प्रदान की गईं और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार केवल दो अभियुक्तों यानी गुलाम नबी गाइड और वसीम अहमद मलिक, वर्तमान उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाया गया, जबकि अन्य फरार रहे।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य निम्नलिखित पहलुओं को साबित करने के लिए था, अर्थात्ः क) कि विचाराधीन स्थानों पर सुबह 10.20 बजे 26.01.1995 पर तीन बम विस्फोट हुए थेः यानी मंच के पास और एम. ए. एम. स्टेडियम में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के स्थान पर और स्टेडियम के बाहर मुख्य सड़क पर. ख) इस तरह के बम विस्फोटों के समय, बड़ी भीड़ जमा हो गई थी जब राज्यपाल गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे. ग) इसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की मौत हो गई और अठारह लोगों को गंभीर चोटें आईं और समारोहों में व्यवधान पैदा हुआ. घ) कि

विचाराधीन कार्य एक आतंकवादी कार्य था, अधिनियम के अर्थ के भीतर. ङ) कि यह अदालत के समक्ष मुकदमा चलाए जा रहे अभियुक्त और फरार अभियुक्त द्वारा रची गई साजिश का कार्य था और च) अदालत के समक्ष अभियुक्त की भागीदारी को पूरी तरह से बनाया गया था।

6. विभिन्न गवाहों से पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को स्थापित करने के लिए सामग्री पेश की गई। चूँकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित पहलुओं (ए) से (डी) को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए हम उक्त पहलुओं (ए) से (डी) से संबंधित साक्ष्य से निपटने से बचते हैं। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि यह एक आतंकवादी कृत्य था, जिसमें आम लोगों और विशेष रूप से सभा में इकट्ठा हुए लोगों को आतंकित करने के विचार से बम विस्फोट किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की जान चली गई और अठारह लोग घायल हो गए, हम पहलुओं (ई) से (एफ) यानी विचाराधीन अधिनियम में आरोपी की भूमिका के संबंध में चर्चा को सीमित करते हैं। निचली अदालत ने खुद को इस सवाल तक सीमित कर लिया था कि क्या उत्तरदाताओं की भागीदारी की गई थी या नहीं।

7. प्रत्यर्थियों की भागीदारी को घर लाने के लिए अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज मोहम्मद इरफान और गुलाम नबी के इकबालिया बयानों पर भरोसा किया। इस तरह के इकबालिया बयानों

और इन अभियुक्तों के बयानों के अलावा कुछ तथ्यों की बरामदगी के लिए, कोई प्रत्यक्ष सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा सका। अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य रूप से जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः ए) हिरासत में रहते हुए, आरोपी मोहम्मद इरफान ने पूछताछ के बाद तीन खुलासा बयान दिए, "ईएक्सपीडब्ल्यू सी बीडी/2, ईएक्सपीडब्ल्यू-एस/3 और ईएक्सपीडब्ल्यू-एस/2"। जाँच अधिकारी, पीडब्लू 86, हरमन सिंह की गवाही से पता चलता है कि इन प्रकटीकरण बयानों के अनुसार दो खुरपा बरामद किए गए थे और उस दुकान की पहचान भी की गई थी जहाँ से एक खुरपा खरीदा गया था। उन खुरपाओं की पहचान अदालत में की गई थी। इस तरह के प्रकटीकरण और परिणामी वसूली के तथ्य का समर्थन पंच गवाह पी. डब्ल्यू. 23 एस. के. सूडान और पी. डब्ल्यू. 24 गौतम गोयल ने भी किया। पी. डब्ल्यू. 67 राजेश कुमार, इंस्पेक्टर, सी. बी. आई. ने भी इसी तरह की गवाही दी।

बी) 22.4.1995 को एक अन्य खुलासा बयान "EXPWBR" आरोपी मोहम्मद इरफान द्वारा दिया गया था जिससे जब्त ज्ञापन Ext.PW/BR/1 के माध्यम से एक बम की बरामदगी हुई। उस ओर से पीडब्लू 86 के सबूतों पर भरोसा किया गया था-हरभजन सिंह, पीडब्लू 67 राजेश कुमार और पंच गवाह पीडब्लू 26 बी. आर. सराफ।

सी) 22.04.1995 पर मोहम्मद इरफान ने इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त की और पुलिस अधीक्षक पीडब्लू 2 शरद कुमार के सामने पेश किया गया। पीडब्लू 2 शरद कुमार ने आरोपी को चेतावनी दी कि कबूलनामे का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है और उसे सोचने का समय भी दिया। आरोपी को फिर से 23.04.1995 पर गवाह के सामने पेश किया गया, जिस तारीख को आरोपी मोहम्मद इरफान का इकबालिया बयान Ext.PW-SK-3 पीडब्लू 2 शरद कुमार द्वारा दर्ज किया गया था। स्वीकारोक्ति का सार और उसमें प्रकट किए गए तथ्यों पर पहले चर्चा की गई है। मोहम्मद इरफान के इकबालिया बयान में कबूल करने वाले आरोपी के साथ-साथ सह-आरोपी की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

घ) गुलाम नबी गाइड की गिरफ्तारी के बाद, उनकी हिरासत 04.12.1995 पर सी. बी. आई. को दी गई। उसने एक इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि गुलाम नबी गाइड को पी. डब्ल्यू. 1 एस. के. भटनागर, पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. के सामने 16.12.1995 पर पेश किया गया था। गवाह ने आरोपी को वैधानिक चेतावनी दी और उसे पुनर्विचार करने का समय भी दिया। अभियुक्त के सामने सवाल रखे गए जिनका उसने जवाब दिया और गवाह द्वारा हिंदी में इसका सही रिकॉर्ड बनाया गया। गवाह के अनुसार उसने आरोपी को सब कुछ समझाया था

और बयान दर्ज करने के बाद, बयान पर आरोपी के अंगूठे का निशान लिया गया था। अभियुक्त को फिर से 18.12.1995 पर गवाह के सामने पेश किया गया और इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, गवाह द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया। बयान दर्ज करने के बाद, इसे पढ़ा गया और आरोपी को बयान को समझने के लिए कहा गया, जहां बयान को सच स्वीकार करने के बाद आरोपी ने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। ई) कबूल करने वाले आरोपी गुलाम नबी गाइड को जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 19.12.1995 पर पेश किया गया था। एक सीलबंद लिफाफे में मूल रूप में इकबालिया बयान भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे जम्मू के नामित न्यायालय में आगे प्रस्तुत किया गया था। पत्र का मूल पाठ इस प्रकार थाः

"महोदय, कृपया आर. सी. मामले में टाडा अधिनियम की धारा 15 टाडा अधिनियम RC. 1(S)/95/SIU.V के तहत दर्ज आरोपी गुलाम नबी गाइड का मूल बयान (सीलबंद) नामित न्यायालय, जम्मू के माननीय न्यायाधीश को आगे प्रस्तुत करने के लिए इसके साथ संलग्न करें। आरोपी को भी लाया गया है।

आवेदक

एस. डी./-

19.12.95

(एस. के. भटनागर)

पुलिस अधीक्षक सी. बी. आई.,

SIC. II, नई दिल्ली

च) उसी दिन, जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः "टाडा के तहत नामित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को मूल रूप से प्रस्तुत किया गया। मुहरबंद लिफाफा इसके साथ संलग्न है।

एसडी/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जम्मू

8. निचली अदालत ने दोनों प्रतिवादियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। बम विस्फोट के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बिल्कुल भी विवादित नहीं था। हालाँकि, निचली अदालत ने गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयान के संबंध में सबूत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इकबालिया बयान हिंदी में दर्ज किया गया था, न कि आरोपी की भाषा में। इसने पाया कि

अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 15 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था और इसलिए, आरोपी गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयान को खारिज करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में निचली अदालत की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार थींः पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में इकबालिया बयान हिंदी में दर्ज किया गया है न कि आरोपी की भाषा में। जांच अधिकारी पीडब्लू हभाजन राम ने कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि आरोपी गुलाम नबी हिंदी जानते हैं या नहीं। किसी भी मामले में, आरोपी गुलाम नबी पाकिस्तानी नागरिक होने के कारण, उनकी भाषा हिंदी नहीं हो सकती। फिर भी, पीडब्लू सुशील कुमार, जो आरोपी गुलाम नबी के इकबालिया बयान के रिकॉर्डिंग अधिकारी हैं, ने कहा है कि आरोपी ने उर्दू में बयान दिया था और उसने वही हिंदी में लिखा था। उक्त गवाह द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि उर्दू में अभियुक्त का इकबालिया बयान दर्ज करना व्यावहारिक क्यों नहीं था। फिर भी, रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि पीडब्लू सुशील कुमार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। बल्कि, अभिलेख से पता चलता है कि उक्त गवाह सुशील कुमार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग करता है। ई. एक्स. पी. डब्ल्यू. एस. के./III द्वारा सी. जे. एम. को लिखे गए पत्र से यह स्पष्ट है जब उन्होंने स्वीकारोक्ति को नामित अदालत में भेजा था। और अंत में, नामित न्यायालय की भाषा उर्दू या अंग्रेजी है।

9. निचली अदालत ने आगे कहा कि इस तरह के इकबालिया बयान के अलावा गुलाम नबी गाइड के खिलाफ और कुछ नहीं था, आरोपी बरी होने का हकदार था। अन्य अभियुक्त वसीम अहमद ने कोई इकबालिया बयान नहीं दिया था और उसके खिलाफ मामला पूरी तरह से सह-अभियुक्त गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयान पर निर्भर था। नतीजतन, आरोपी वसीम अहमद को भी बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार दोनों अभियुक्तों को अपने फैसले और दिनांक 02.03.2009 के आदेश के माध्यम से बरी कर दिया, जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

10. वर्तमान अपील के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी वसीम अहमद मलिक को विधिवत सेवा दी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी वकील को शामिल नहीं करने का फैसला किया। यह बताया गया था कि प्रतिवादी गुलाम नबी गाइड पाकिस्तान में रह रहे थे और उन्हें भारत सरकार के संबंधित कार्यालय के माध्यम से सेवा प्रदान की गई थी। हालाँकि, गुलाम नबी गाइड की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, हालांकि विधिवत सेवा दी गई थी। नतीजतन, श्री दुष्यंत पाराशर, विद्वान अधिवक्ता से सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के निर्देशों के तहत प्रतिवादी गुलाम नबी गाइड के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। चूंकि आदेश की तारीख 12.03.2015 तक प्रतिवादी वसीम

अहमद मलिक के लिए कोई उपस्थिति नहीं थी, इसलिए श्री दुष्यंत पाराशर ने इस अदालत से अनुरोध किया कि वे उक्त वसीम अहमद मलिक का प्रतिनिधित्व न्यायमित्र के रूप में करें। श्री दुष्यंत पाराशर द्वारा दी गई सहायता के लिए हमें अपनी सराहना दर्ज करनी चाहिए।

11. अपील के समर्थन में श्री पी. के. डे, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया: (ए) अधिनियम की धारा 15 के तहत आरोपी का इकबालिया बयान एक ठोस सबूत है और अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक आरोपी को दोषी ठहराने की नींव बना सकता है। (बी) इस तरह के कबूलनामे को, अधिनियम की धारा 15 में निर्धारित शर्तों के अधीन, सह आरोपी के खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है और उसे दोषी ठहराए जाने का आधार बनाया जा सकता है। (सी) पीडब्लू1 एस. के. भटनागर द्वारा दर्ज किए गए कबूलनामे से खुद पता चलता है कि पूरा बयान कबूल करने वाले आरोपी को पढ़ा गया था और उसके बाद ही बयान के तहत कबूल करने वाले आरोपी के अंगूठे की छाप ली गई थी। चूँकि इस तरह की बातचीत के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा हिंदी थी जिसे कबूल करने वाला आरोपी समझ सकता था, इसलिए बयान की रिकॉर्डिंग हिंदी में की गई थी और ऐसी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 15 के अनुरूप थी। (घ) अंत में, स्वीकारोक्ति दर्ज करने के तुरंत बाद, कबूल करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश

किया गया। एक सीलबंद लिफाफे में इकबालिया बयान को भी नामित न्यायालय में आगे भेजने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, दिशा-निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। न्यायमित्र श्री दुष्यंत पाराशर ने अपील के तहत फैसले का समर्थन करने का प्रयास किया। विद्वान न्यायमित्र ने उचित रूप से स्वीकार किया कि स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाले दस्तावेज़ से ही पता चलता है कि पूरा बयान पढ़ा गया था और स्वीकारोक्ति करने वाले आरोपी को समझाया गया था। उन्होंने आगे निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि जब पीडब्लू1 एस. के. भटनागर पक्ष में थे, तब इस मुद्दे पर कोई प्रभावी जिरह नहीं हुई थी।

12. अधिनियम की धारा 15 (1) स्पष्ट रूप से एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए आरोपी के इकबालिया बयान को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति, सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य बनाती है। अधिनियम की धारा 15 (1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 मामले में विशेष रूप से अधिनियम की धारा 15 (2) में वैधानिक दायित्व और क्रमशः पैरा 258 और 259 में टाडा नियमों के नियम 15 में लगाई गई शर्तों का उल्लेख किया और फिर पैरा 263 में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े।

एक सह-अभियुक्त के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत इस तरह के स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की सीमा पर इस न्यायालय द्वारा राज्य बनाम नलिनी और अन्य वाधवा जे. में पैरा 424 में विचार किया गया था। उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैंः वर्तमान मामले में अभियुक्त के इकबालिया बयान स्वेच्छा से और वैध रूप से किए जाने चाहिए और टाडा की धारा 15 के तहत एक अभियुक्त का इकबालिया बयान एक सह-अभियुक्त के खिलाफ एक ठोस सबूत के रूप में स्वीकार्य है। हालाँकि, महत्वपूर्ण साक्ष्य का मतलब आवश्यक रूप से पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह सबूत की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। इस बारे में कि स्वीकारोक्ति के साथ क्या मूल्य जोड़ा जाना है, साक्ष्य की सराहना के क्षेत्र में आएगा। विवेक के मामले में, अदालत कुछ पुष्टि की तलाश कर सकती है यदि किसी सह-अभियुक्त के खिलाफ स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जाना है, हालांकि यह फिर से साक्ष्य के मूल्यांकन के दायरे में होगा। न्यायमूर्ति कादरी ने पैरा 706 में इसी तरह की चेतावनी दी हैः

"706. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के साक्ष्य को शपथ पर देने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे अभियुक्त की उपस्थिति में दिया जाता है, और इसकी सत्यता का परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि एक साथी का साक्ष्य इन कमियों से मुक्त है, फिर भी एक साथी वह व्यक्ति है जिसने

अपराध करने में भाग लिया है, खुद को बचाने के लिए, अपने पूर्व सहयोगियों को धोखा दिया और खुद को एक सुरक्षित तख्त पर रखा-"एक ऐसी स्थिति जिसमें वह अभियोजन पक्ष के पक्ष में एक मजबूत पूर्वाग्रह रखने में शायद ही विफल हो सकता है", आरोपी की स्थिति जिसने एक सह आरोपी को निहित करते हुए इकबालिया बयान दिया है, वह यह है कि उसने खुद को एक ही तख्त पर रखा है और इस प्रकार वह अपने कबूलनामे के आधार पर सह आरोपी के साथ डूब जाता है या नौकायन करता है। इन कारणों से, जहां तक सह-अभियुक्त के खिलाफ अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के उपयोग का संबंध है, विवेक का नियम न्यायिक विवेकाधिकार को आगाह करता है कि इस पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य द्वारा आम तौर पर पुष्टि नहीं की जाती।

13. कानून में यह तय स्थिति है कि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत दर्ज एक स्वीकारोक्ति निर्माता, उसके सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमे में स्वीकार्य है, जो धारा 15 (1) के प्रावधान में निर्धारित शर्त के अधीन है। इस तरह के कबूलनामे को सबूत के मूल टुकड़े के रूप में लिया जाता है और निर्माता, सह-आरोपी, उकसाने वाले या साजिशकर्ता को दोषी

ठहराने के लिए आधार या आधार बन सकता है। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा सावधानी बरतने की बात यह है कि, जहाँ तक सह-अभियुक्त के विरुद्ध किसी अभियुक्त के कबूलनामे का उपयोग करने का संबंध है, विवेक के नियम के अनुसार न्यायालय को उस पर भरोसा नहीं करना होगा जब तक कि आम तौर पर रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

14. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम टाडा नियमों के नियम 15 (1) की आवश्यकताओं और मामले के तथ्यों की ओर रुख करते हैं। नियम 15 (1) में कहा गया है कि स्वीकारोक्ति हमेशा उस भाषा में दर्ज की जाएगी जिसमें ऐसी स्वीकारोक्ति की जाती है और यदि वह व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए या नामित न्यायालय की भाषा में उपयोग की जाएगी। "निश्चित रूप से" अभिव्यक्ति से ही पता चलता है कि नियम के तहत आवश्यकता विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। वर्तमान मामले में रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है कि कबूल करने वाले आरोपी गुलाम नबी को पीडब्लू1 एस. के. भटनागर के सामने 16.12.1995 पर पेश किया गया था, जिसे वैधानिक चेतावनी दी गई थी और सोचने का समय दिया गया था। उन्हें सब कुछ समझाया गया और उसके बाद ही उनके अंगूठे का निशान लिया गया। अगले अवसर पर जब इकबालिया बयान देने वाले आरोपी को फिर से गवाह के सामने पेश

किया गया, तो इकबालिया बयान दर्ज होने के तुरंत बाद उसे फिर से समझाया गया, पढ़ा गया और उसके बाद ही अंगूठे का निशान लिया गया। इन दो अवसरों पर रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी स्तर पर, न ही उस स्तर पर जब गवाह बक्से में था, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, या यहां तक कि एक सुझाव भी है कि कबूल करने वाले आरोपी को स्वीकारोक्ति की सामग्री को समझने के लिए नहीं बनाया गया था। स्वीकारोक्ति की सामग्री से यह भी पता चलता है कि कई दावे कबूल करने वाले आरोपी के लिए व्यक्तिगत हैं जो रिकॉर्डिंग अधिकारी के साथ उचित बातचीत के बाद ही एकत्र किए जा सकते हैं।

15. स्वीकार करने वाले आरोपी और रिकॉर्डिंग अधिकारी के बीच संचार के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है, हिंदी भाषा में स्वीकारोक्ति की ऐसी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से नियम की आवश्यकता के अनुरूप है। निचली अदालत द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि गुलाम नबी पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते उनकी भाषा उर्दू होनी चाहिए और इसलिए उर्दू के अलावा किसी अन्य भाषा में स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग को अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए, गलत है। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि कबूल करने वाले आरोपी को पूछताछ की रेखा समझ में नहीं आई या रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद उसे कबूलनामे की सामग्री को समझने के लिए नहीं बनाया गया था। हमारे विचार में इस

संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन पूरी तरह से गलत और अभिलेख के खिलाफ है।

16. हमें पीडब्लू 1 एस. के. भटनागर द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज करने में कोई कमजोरी नहीं मिलती है। अभियुक्त गुलाम नबी का इकबालिया बयान इस अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया गया था और यह वैधानिक आवश्यकता के अनुसार था। स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य मानते हुए, हमने स्वीकारोक्ति की सामग्री का अध्ययन किया है जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति करने वाले आरोपी के अपराध और साजिश रचने से लेकर उसे लागू करने तक उसकी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। कबूल करने वाले आरोपी ने साजिश रचने के बाद से विभिन्न चरणों के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे कबूल करने वाले आरोपी ने सीमा पार से विस्फोटक सामग्री को ले जाने में मदद की थी और फिर इसे गड्ढों में रखा था, स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर मुख्य सड़क पर खोदा गया था। बमों का परिणामी विस्फोट जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोहों के साथ किया गया था, निश्चित रूप से समारोहों को बाधित करने और आम लोगों और विशेष रूप से उत्सव के समय एकत्र हुए लोगों को आतंकित करने के लिए बनाया गया था। इसलिए, हम मानते हैं कि स्वीकारोक्ति से, साजिश, निष्पादन और उसे सुगम बनाने में आरोपी गुलाम नबी की संलिप्तता पूरी तरह से सामने

आती है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा है और उसकी दोषसिद्धि इस तरह के स्वीकारोक्ति पर ही आधारित हो सकती है। इसलिए हम गुलाम नबी गाइड को उन अपराधों का दोषी मानते हैं जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

17. हालाँकि, अन्य अभियुक्तों, अर्थात् वसीम अहमद मलिक के संबंध में, गुलाम नबी गाइड के इकबालिया बयान के अलावा, जो कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जो साजिश और उसके निष्पादन में उसकी भूमिका के संबंध में पुष्टि कर सके। हमने सामग्री पर बारीकी से विचार किया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो इस तरह की पुष्टि कर सके। विवेक के नियम के अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राज्य बनाम नलिनी (उपरोक्त) के मामले में उजागर किया गया है, हम उक्त वसीम अहमद मलिक के संबंध में दर्ज बरी होने के निष्कर्ष को उलटने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। इसलिए हम वसीम अहमद मलिक को बरी करने के फैसले की पुष्टि करते हैं, जैसा कि निचली अदालत ने उन अपराधों के संबंध में दर्ज किया है जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

18. नतीजतन, इस अपील की आंशिक रूप से अनुमति है। वसीम अहमद मलिक के बरी होने की पुष्टि हो गई है। हालाँकि, गुलाम नबी के

संबंध में बरी होने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और कहा गया है कि आरोपी गुलाम नबी गाइड को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। यह निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ एक अपील होने के कारण, हम सजा के मुद्दे पर उक्त गुलाम नबी गाइड को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त गुलाम नबी गाइड को इस अदालत के समक्ष पेश करें ताकि उन्हें दी जाने वाली सजा पर इस अदालत को संबोधित करने का उचित अवसर दिया जा सके।

19. अपील की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि गुलाम नबी गाइड को तुरंत हिरासत में लिया जाए और सजा पर सुनवाई के लिए इस अदालत के समक्ष लाया जाए।

20. हम उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को श्री दुष्यंत पाराशर को इस न्यायालय को प्रदान की गई सहायता के लिए पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने का भी निर्देश देते हैं।

देविका गुजराल

अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।